Study of sustainable development process for quality education in Sikar district

सीकर जिले में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सतत विकास प्रक्रिया का अध्ययन

Vinod Kumar Saini[1], Dr. Sunita Kumari[2]

[1]Research Scholar, Sunrise University, Alwar, Rajasthan
[2]Research Supervisor, Sunrise University, Alwar, Rajasthan

सारांश

ग्रामीण स्कूल प्रणालियों में स्थानीय राजनीतिक गतिशीलता के माध्यम से काम करना स्कूल नेतृत्व के दायरे में आता है। शैक्षिक प्रक्रिया में स्कूल नेता की भागीदारी के हर स्तर पर स्थानीय राजनीति मौजूद होती है, स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक। ग्रामीण विद्यालय नेता के सामने चुनौती इस वास्तविकता को स्वीकार करने की है कि स्थानीय राजनीति दैनिक दिनचर्या का एक हिस्सा है और यह सुनिश्चित करने के लिए उस प्रक्रिया के साथ काम करना है कि शैक्षिक रूप से सही निर्णय अंततः सीकर जिले के ग्रामीण विद्यालय के छात्रों के लिए परिणामित हों। शब्द "स्थानीय राजनीति" आमतौर पर संगठनात्मक संदर्भ में पाया जाता है, और अक्सर इसके साथ एक नकारात्मक अर्थ होता है। तो, वास्तव में स्थानीय राजनीति क्या है, राजनीति कहाँ पाई जाती है और राजनीति को कैसे पहचाना जाता है? राम्से (2006) के अनुसार, "जहाँ भी सत्ता होनी है, संसाधनों का बंटवारा करना है, अर्जित की जाने वाली मान्यता है, या दलाली करने के लिए प्रभाव है, वहाँ राजनीति है"। इसके अलावा, रैमसे (2006) ने कहा, "जहां भी नेता और अनुयायी हैं, वहां राजनीति है"। इस प्रकार, किसी भी स्कूल प्रणाली में, राजनीति हर जगह होनी चाहिए, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सब कुछ बुरा ही हो।

मुख्यशब्द ग्रामीण, स्कूल, राजनीतिक, गतिशीलता, शैक्षिक प्रक्रिया, सुनिश्चित, स्थानीय, राजनीति

प्रस्तावना

2014 में, राजस्थान सरकार ने एक नई पहल, राजस्थान आदर्श योजना की घोषणा की, जो राज्य भर में 9,895 ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक में एक आदर्श (हिंदी "आदर्श") स्कूल स्थापित करेगी (एक ग्राम पंचायत में शासित गांवों का एक समूह शामिल है) एकल ग्राम परिषद द्वारा)। राज्य

ने एक आदर्श स्कूल को एक एकीकृत प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के रूप में परिभाषित किया जो बड़ा, बच्चों के अनुकूल और पूरी तरह से स्टाफ वाला है; सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करता है। यह मॉडल सरकारी स्कूल आसपास के अन्य स्कूलों के लिए एक खाका के रूप में काम करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि कम से कम एक पूरी तरह से सुसज्जित, एकीकृत स्कूल क्षेत्र के बच्चों के लिए सुलभ हो। राजस्थान के शिक्षा सचिव नरेश गंगवार ने इस पहल की अगुवाई की। अपनी शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए राज्य की प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर, क्रमशः 2015 और 2016 में डेल फाउंडेशन और सीएसएफ ने सरकार के प्रयासों का समर्थन करना शुरू कर दिया। सरकार को अपनी दृष्टि को लागू करने में मदद करने और सरकार को रणनीतिक और परियोजना प्रबंधन सहायता प्रदान करने के लिए बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (*BCG)* को वित्तपोषित करने के लिए परोपकारी लोग प्रतिबद्ध हैं। राजस्थान आदर्श योजना के माध्यम से, सरकार का लक्ष्य 2018 के अंत तक कम से कम 4.6 मिलियन बच्चों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। यह प्रयास साहसिक है, न केवल इसके पैमाने के कारण, बल्कि इसलिए भी कि इसमें महत्वपूर्ण व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता है: हितधारक शिक्षा व्यवस्था में हर स्तर पर शिक्षकों से लेकर सरकारी अधिकारियों तक को सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता बदलने में अपना योगदान देना होगा। यह पहल आदर्श स्कूलों को "मॉडल" के रूप में भी देखती है जो अंततः राज्य के सभी स्कूलों के लिए मानक निर्धारित करेंगे। पहल की महत्वाकांक्षा को देखते हुए, साझेदारों के दृष्टिकोण से आरंभ करने की सबसे बड़ी चुनौती, शिक्षा प्रणाली के मूल घटकों को पहचानने और समझने में थी, जिन्हें बहाल करने या यहां तक कि पुनर्कल्पित करने की आवश्यकता थी, उनका चयन करना और एक ऐसी योजना बनाना जो सरकार को जीवन में ऐसा परिवर्तन लाओ। डेल फाउंडेशन और सीएसएफ इस कार्यक्रम का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि शिक्षा में बड़े पैमाने पर प्रभाव प्राप्त करने के लिए सिस्टम सुधार महत्वपूर्ण है। डेल फाउंडेशन के भारत कार्यक्रमों का निर्देशन करने वाले देबाशीष मित्तर कहते हैं, "इस देश में लाखों और करोड़ों बच्चे वास्तव में वह परिदृश्य है जिसे हम संबोधित करना चाहते हैं।" "यह किनारे पर छोटे बदलावों के बारे में नहीं है।"

राजस्थान आदर्श योजना ने कल्पना की कि 2018 के अंत तक, राजस्थान की सभी ग्राम पंचायतों में एक पूरी तरह से काम करने वाला आदर्श स्कूल होगा। प्रशिक्षित शिक्षकों के एक कर्मचारी के साथ, प्रत्येक स्कूल ग्रेड 1-12 में छात्रों के लिए बेहतर सीखने के परिणाम तैयार करेगा। राजस्थान आदर्श योजना ने स्कूल स्तर के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए सुशासन और उत्तरदायित्व के महत्व को भी मान्यता दी है। छात्रों के सीखने को आगे बढ़ाने की दिशा में गतिविधियों के अलावा, यह पहल उन तंत्रों को भी स्थापित करेगी जो शिक्षकों, स्कूल के नेताओं और सरकारी अधिकारियों को इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जवाबदेह ठहराते हैं। इस तरह

के एक उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहल ने राज्य सरकार, दो परोपकारी नींव, बीसीजी, और स्थानीय सामुदायिक समूहों के एक मजबूत नेटवर्क पर काम किया। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई गतिविधियाँ शुरू की हैं कि पहल शिक्षा प्रणाली को समग्र रूप से बदल दे। मुख्य गतिविधियों में शामिल हैं: 1) छोटे प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को ग्रेड 1-12 के लिए एक आदर्श विद्यालय के रूप में कार्य करने के लिए एकीकृत करना; 2) इन स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार; 3) शिक्षकों और अन्य सहायक कर्मचारियों को ओवरस्टाफ से कम स्टाफ वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित करने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया बनाकर आदर्श स्कूलों में पूरी तरह से स्टाफिंग; 4) डेटा को ट्रैक करने और छात्र, शिक्षक, स्कूल, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर जवाबदेही बनाने के लिए एक ऑनलाइन, रीयल-टाइम प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) स्थापित करना; और 5) गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य पहल को संस्थागत बनाना, एक ऐसा मॉडल जहां शिक्षक लगातार प्रत्येक छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हैं और प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं और सीखने की शैली के अनुरूप प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं। महत्वपूर्ण रूप से, एमआईएस पर एकत्र किए गए डेटा का उपयोग रिपोर्ट बनाने के लिए किया जाता है जो आदर्श बनने की दिशा में जिलों और स्कूलों को उनकी प्रगति पर रैंक करता है। बीसीजी, अपने हिस्से के लिए, राज्य और जिला दोनों स्तरों पर योजना और प्रबंधन में विशेषज्ञता प्रदान करता है। राज्य स्तर पर, बीसीजी पहल को डिजाइन करने और लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करता है, प्रमुख राज्य सरकार के प्रतिनिधियों (जैसे मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव) के साथ काम करता है, और प्रगति की निगरानी करता है। जिला स्तर पर, बीसीजी पहल के रोल आउट में सहायता करता है। जैसे-जैसे यह पहल अपनी समाप्ति तिथि के करीब आ रही है, कंसल्टेंसी इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए जिला अधिकारियों की क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। दोनों परोपकारी भागीदार पहल में योगदान करते हैं। डेल फाउंडेशन यह साझा करता है कि शिक्षा पहलों का विस्तार करने और उन्हें बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है, जिसे इसने विश्व स्तर पर और पूरे भारत में शिक्षा पहलों का समर्थन करके हासिल किया है। भारत भर में अन्य शिक्षा अनुदानों के प्रबंधन से अपने अनुभव को आकर्षित करते हुए, सीएसएफ बीसीजी और सरकार को छात्र आकलन और शिक्षाशास्त्र जैसे विशिष्ट क्षेत्रों पर सलाह देता है। इस पहल का समर्थन करके, *CSF* इस बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक है कि शिक्षा प्रणाली को कैसे बेहतर बनाया जाए और अन्य राज्यों में इसी तरह के कार्यक्रम शुरू किए जाएं। आज तक, डेल फाउंडेशन ने पहल के लिए *INR* 27 करोड़ (4.1 मिलियन अमरीकी डालर) दिए हैं और *CSF* ने *INR* 152 लाख (*USD* 225,000) का योगदान दिया है। पहल जमीनी स्तर पर भी चल रही है। माता-पिता और समुदाय के अन्य सदस्य स्कूल प्रबंधन समितियों में भाग लेते हैं, स्कूल के कामकाज की निगरानी करते हैं और स्कूल अधिकारियों को लक्ष्यों के प्रति जवाबदेह ठहराते हैं।

विद्यालयों में राजनीति की भूमिका

राजनीति एक अध्ययन और कौशल दोनों है कि कैसे शक्ति का प्रयोग किया जाता है, और किसके द्वारा (और किसके लाभ के लिए), सार्वजनिक शक्ति के प्रशासन के माध्यम से, लोगों के मामलों का प्रबंधन किया जाता है। राजनीति सार्वजनिक शिक्षा के संचालन का एक अभिन्न अंग है। शिक्षा में राजनीति केवल स्कूल बोर्ड के सदस्यों या स्थानीय स्कूल परिषदों के चुनाव के तरीकों के बारे में नहीं है बल्कि यह दिन-प्रतिदिन के जीवन का एक अभिन्न अंग है। राजनीतिक गतिविधि दुर्लभ संसाधनों के आवंटन पर बातचीत करने और यह तय करने के बारे में है कि किसे क्या मिलता है। लेकिन सभी राजनीतिक गतिविधियां एक जैसी नहीं होतीं। स्कूलों में राजनीतिक संघर्षों के अलग-अलग विचार और उद्देश्य होते हैं।

स्कूल परिषदों और समूहों की शुरुआत से न केवल एक स्वस्थ छात्र आवाज पैदा हुई है बल्कि यह भविष्य में मतदान के लिए युवाओं के दिमाग को आकार देने का एक उपकरण भी बन गया है। ऐसी परिषदें युवाओं की प्रभावी भागीदारी में बाधा बन सकती हैं। युवा लोग आज पहले की तुलना में अधिक सूचित और नागरिक-दिमाग वाले हैं और छात्र संगठन परिसर में कई राय और विभिन्न राजनीतिक हितों के लिए अवसर प्रदान करते हैं। छात्र मंचों, अध्ययन समूहों और सम्मेलनों सहित व्यापक कार्यक्रम में भाग लेते हैं। लेकिन जहां युवा की कमी है वह सही परिप्रेक्ष्य देखने की मानसिकता और परिपक्वता है।

यह सच है कि विश्वविद्यालय और अन्य राजनीतिक संगठनों में नेतृत्व की स्थिति लेने के इच्छुक लोगों के लिए बहुत सारे अवसर हैं। इसके निर्वाचित सदस्य प्रशासन और छात्र समुदाय के प्रतिनिधि होते हैं। और कभी-कभी केवल प्रतिनिधि। ये कई कार्यक्रमों और सेवाओं को प्रायोजित करने के लिए भी जिम्मेदार हैं जो छात्रों के दिल के सबसे करीब और प्रिय हैं जैसे संगीत कार्यक्रम, समारोह आदि। लेकिन राजनीति का एक और पहलू यह है कि छात्र कैंपस के बाहर विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों में खुद को शामिल करते हैं और अपने परिणाम या करियर को खराब करते हैं। . छात्रों को अपने शैक्षिक जीवन को खराब होने से बचाने के लिए उन्हें अपने देश की सक्रिय राजनीति में सक्रिय भागीदारी से दूर रखना चाहिए। हालांकि, उन्हें आवश्यक रूप से अपने देश में राजनीतिक विकास के बारे में जागरूकता होनी चाहिए। छात्र का जीवन जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है जिसमें छात्रों को किसी भी अन्य गतिविधियों की तुलना में अपनी शिक्षा को अधिक प्राथमिकता देनी पड़ती है, राजनीति में उनकी सक्रिय भागीदारी से उनकी खुद की पढ़ाई का नुकसान होता है, जो उनके लिए अधिक आवश्यक है। विद्यार्थी की यह अवस्था एक बार गुजर जाने के बाद फिर वापस नहीं आती और अगर हो भी जाती है तो भी चीजें पहले जैसी नहीं रहतीं। आज के विद्यार्थी कल देश के कर्णधार हैं। इसलिए

उन्हें देश की राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी होनी चाहिए। देश की राजनीति में सक्रिय भागीदारी करने से पहले उन्हें हमारे महान नेताओं और देश के विकास के लिए प्रत्येक पार्टी के योगदान के बारे में अधिक जानना चाहिए। सक्रिय भागीदारी उचित नहीं है क्योंकि यह उनकी पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। सीधे शब्दों में कहें तो छात्रों को खुद को इस गंदे खेल से दूर रखना चाहिए। उन्हें अपनी वांछित योग्यता पूरी करने के बाद ही राजनीति में प्रवेश करने के बारे में सोचना चाहिए।

सीकर जिले में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य नीति के कार्यान्वयन पर स्थानीय राजनीति का प्रभाव

सतत विकास लक्ष्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सतत विकास लक्ष्यों के लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले कारकों में से एक है। समस्या यह है कि सतत विकास लक्ष्य स्थानीय स्तर की नीतियों को एकीकृत करने में महत्वाकांक्षी दिखते हैं जो राजनीतिक हितों के प्रति उत्तरदायी हैं। अनुसंधान ने साक्षात्कार डेटा और प्रश्नावली की खोज, अन्वेषण की मिश्रित विधि का उपयोग किया। परिणामों से पता चला कि सतत विकास लक्ष्यों का कार्यान्वयन स्थानीय लोकतंत्र से काफी प्रभावित था। सतत विकास लक्ष्यों के प्रचार के कार्यान्वयन के लिए स्थानीय राजनीति और लोकतंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है, जिसमें शामिल हैं; स्थानीय राजनीति की गुणवत्ता, समुदाय की भूमिका, राजनीतिक दल, मीडिया नियंत्रण और सार्वजनिक बैठकें। नीति कार्यान्वयन पर स्थानीय लोकतंत्र का प्रभाव *51.5%* है। *0.187* के मान के साथ सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन पर नीति कार्यान्वयन का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सतत विकास लक्ष्यों *-4* के प्रचार पर स्थानीय लोकतंत्र और नीति कार्यान्वयन का प्रभाव *64.2%* है और शेष *35.8%* अन्य कारकों से प्रभावित है। इस अध्ययन का उद्देश्य इंडोनेशिया के मदुरा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्यों को लागू करने में शिक्षा नीति और प्रगति के लिए निहितार्थ वाले लोकतंत्र और स्थानीय राजनीति की स्थितियों की व्याख्या करना है। विश्व स्तर पर, सतत विकास लक्ष्य *2015* में आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विकास के तीन आयामों को प्राप्त करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण के रूप में शुरू हुए। सतत विकास लक्ष्यों में *17* वैश्विक कार्यक्रम हैं और सतत विकास के लिए एक रणनीतिक एजेंडा माना जाता है साथ ही परिवर्तनकारी मानव विकास की दिशा में एक नया युग सतत विकास लक्ष्यों का एजेंडा यह सुनिश्चित करता है कि यह सरकार के सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं और भविष्य के हितों के लिए एक एकीकृत प्रतिमान के रूप में दूर करने के लिए अभिनेताओं के बीच एकीकरण के माध्यम से मार्गदर्शन कर सकता है। सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन का अध्ययन शैक्षिक परिप्रेक्ष्य सहित कई दृष्टिकोणों से किया गया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा विश्व स्तर पर और विभिन्न देशों में सतत विकास लक्ष्यों को

बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक केंद्र है। विकासशील देशों में विभिन्न विकास समस्याएं हैं, जो समाज में शिक्षा के स्तर पर बहुत निर्भर हैं। इसलिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वह कुंजी है जो अन्य सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि को सक्षम बनाती है, जिनमें से सबसे अधिक संभावना समाज को गरीबी के चक्र से मुक्त करना, लोगों के बीच सहिष्णुता को बढ़ावा देना और सामाजिक शांति में योगदान देना है। हालाँकि, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नीतियां राजनीतिक स्थिरता और स्थानीय लोकतंत्र पर निर्भर करती हैं जो नीति, प्रशासन और नौकरशाही प्रदर्शन में भूमिका निभाते हैं। शिक्षा में सतत विकास लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय राजनीति की भूमिका और मजबूती की भी आवश्यकता है ताकि सतत विकास लक्ष्यों का कार्यान्वयन सतत विकास लक्ष्यों के संकेतकों और लक्ष्यों को छू सके। सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन को स्थानीय स्तर पर एकीकृत करने की आवश्यकता है, जो कि *Pineda-Escobar* के अनुसार, स्थानीय स्तर पर, सबसे जटिल लक्ष्य है क्योंकि संस्थागत अंतराल और विभिन्न स्थानीय स्थितियां हैं।

ज़िंकर्नगेल और अन्य, कहते हैं कि सतत विकास लक्ष्यों को लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती स्थानीय स्तर पर है, कम से कम स्थानीय नीतियों की प्रासंगिकता और राजनीतिक हितों की प्राथमिकताओं से संबंधित है। स्थानीय स्तर की राजनीतिक प्राथमिकताएँ सतत विकास लक्ष्यों के सफल कार्यान्वयन का समर्थन या नुकसान कर सकती हैं। इस बीच, स्थानीय स्तर की राजनीति लोकतंत्र और स्थानीय सरकार के हितों से जुड़ी है। सामाजिक सेवाओं, शिकायतों और शिक्षा जैसी दैनिक जरूरतों को पूरा करने की प्रक्रिया में एक सार्वजनिक वाहन के रूप में क्षेत्र में राजनीति। स्थानीय राजनीति चलती है और राज्य के "राष्ट्रीय" कार्य करती है जिसे स्थानीय राज्य कहा जाता है।

स्थानीय लोकतंत्र नीतियों और नीतियों के कार्यान्वयन को जन्म देता है जो सार्वजनिक हित के लिए अधिक उन्मुख होते हैं क्योंकि इस प्रक्रिया में ऐसे तत्व भी शामिल होते हैं जो जनता से सीधे जुड़े होते हैं। स्थानीय लोकतंत्र राजनीतिक भागीदारी और नीतियों के लिए और भी अधिक स्थान को प्रोत्साहित करता है, कुलीन निर्णय अधिक प्रभावी नहीं होते हैं, क्योंकि वे जनता के सामूहिक हितों से निकटता से जुड़े होते हैं, ताकि अंत में इसका समृद्धि पर भी प्रभाव पड़े]। हैरी ब्लेयर ने कहा कि स्थानीय लोकतंत्र में 7 (सात) संकेतक हैं जो नौकरशाही और सार्वजनिक नीति को प्रभावित करते हैं। इनमें चुनावी प्रणाली, राजनीतिक दलों की भूमिका, नागरिक समाज, मीडिया, जन शिकायत मंच, जनसभाएं और राय सर्वेक्षण शामिल हैं। स्थानीय लोकतंत्र और सार्वजनिक नीति उन अभिनेताओं से निकटता से संबंधित हैं जो नीतियां बनाने का आधार बनाते हैं। नीति और नीति कार्यान्वयन में शामिल अभिनेता सरकारी अधिकारी, विकास एजेंसियां, सामुदायिक संगठन, व्यापारिक समुदाय, मीडिया, शिक्षाविद, हितधारक और धार्मिक नेता हैं।

इसलिए, स्थानीय लोकतंत्रों में अभिनेताओं के बीच एकीकरण नीति और नीति कार्यान्वयन को प्रभावित करता है। नीति प्रक्रिया की आवश्यकता है कि समुदाय की जरूरतों को पूरा करने वाले परिणामों को प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी प्रक्रिया बनाने के लिए सभी अभिनेता मिलकर काम करें। सतत विकास एक महत्वाकांक्षी रणनीति है जिसके लिए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई की आवश्यकता होती है। इसलिए, लेखक के अनुसार नीति और नीति कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाली स्थानीय राजनीति की स्थिरता अन्य लेखों में नहीं पाई गई है, विशेष रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर सतत विकास लक्ष्यों की नीति से संबंधित। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्यों को बढ़ावा देने को सतत विकास लक्ष्यों के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में नीतियों के निर्माण और नीतियों को लागू करने में स्थानीय राजनीति और लोकतंत्र के पहलुओं से देखा जा सकता है।

यह अध्ययन दो विषयों पर केंद्रित है, अर्थात् स्थानीय राजनीति और नीति कार्यान्वयन, जो दर्शाता है कि दोनों का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने में एक मजबूत संबंध है। गुणात्मक चरण में, प्राथमिक डेटा क्षेत्र अवलोकनों, साक्षात्कारों और प्रलेखन अध्ययनों के माध्यम से एकत्र किए गए थे। फिर त्रिकोणासन प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है, अर्थात् टिप्पणियों और विभिन्न दस्तावेजों, दोनों जर्नल लेखों, सरकारी प्रकाशनों और ई-पुस्तकों से प्राप्त आंकड़ों की तुलना करना। फिर परिणाम और चर्चा प्रस्तुत की जाती है जो सतत विकास लक्ष्यों के लिए नीतियों को लागू करने में स्थानीय राजनीतिक विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करती है।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्यों का कार्यान्वयन

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन को 4 संकेतकों में देखा जा सकता है, जिनमें से सभी के अपने-अपने आइटम हैं। सबसे पहले, शिक्षा की पहुंच, मुफ्त शुल्क, समावेशी शिक्षा और स्कूली शिक्षा की औसत लंबाई में शामिल हैं:

1) स्थानीय सरकार प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल शिक्षा शुल्क निःशुल्क प्रदान करती है। एसएमए स्वतंत्र है लेकिन पूर्वी जावा प्रांतीय सरकार का अधिकार है। केंद्र सरकार दूसरों के बीच शिक्षा की लागत के लिए भी सहायता प्रदान करती है; स्मार्ट इंडियन कार्ड, स्कूल ऑपरेशनल असिस्टेंस (बीओएस) और एजुकेशन ऑपरेशनल असिस्टेंस फीस (बीपीओपीपी)। हालाँकि, कुछ स्कूल अभी भी शैक्षिक सुविधाओं को पूरा करने के लिए माता-पिता से दान लेते हैं। सरकारी सहायता केवल शिक्षकों और शिक्षकों के वेतन के लिए पर्याप्त है। निजी स्कूल अभी भी माता-पिता और पूर्व छात्रों के योगदान पर बहुत कुछ निर्भर करते हैं।

2) 12 साल की अनिवार्य शिक्षा नीति को हासिल नहीं किया गया है। एडी रसियादी (व्यक्तिगत संचार, 2020) के अनुसार सीकर जिले में स्कूली शिक्षा की औसत अवधि केवल 5.45 वर्ष या प्राथमिक विद्यालय के स्नातक हैं। इस बीच सीकर जिले में स्कूली शिक्षा की औसत लंबाई 5.33 वर्ष है या प्राथमिक विद्यालय स्नातक होने तक नहीं है। दो जिलों में स्कूली शिक्षा की कम लंबाई के कारक कम उम्र में विवाह की उच्च दर और शिक्षा जागरूकता की कमी के कारण हैं।

दूसरा, मानव अधिकारों, सहिष्णुता, शांति और संस्कृति के बारे में छात्रों के सीखने और ज्ञान में सतत विकास लक्ष्यों के प्रतिमान की अखंडता। इस्कंदर (जुलाई, 20, 2020) के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों के प्रतिमान में विशिष्ट शिक्षा नहीं है, लेकिन नागरिकता पाठ और पाठ्येतर गतिविधियों जैसे कुछ पाठों में एकीकृत है। अभी भी कई अन्य स्कूल हैं जिन्होंने सतत विकास लक्ष्यों के प्रतिमान के एकीकरण पर ध्यान नहीं दिया है।

तीसरा, श्रम प्रधान शिक्षा पाठ्येतर गतिविधियों से संबंधित है। इस्कंदर (जुलाई, 20, 2020) के अनुसार, जबकि 2020 तक छात्रों के लिए पूरी तरह से कौशल और शिल्प तैयार करने वाले स्कूल केवल मैन सुमनिप हैं, अन्य स्कूल शिल्प और उद्योग के साथ प्रशिक्षण और सहयोग के लिए नए हैं।

चौथा, सीखने की प्रासंगिकता स्कूल के स्नातकों और काम उन्मुख शिक्षण प्रणालियों के काम से संबंधित है। मंसूर (11 सितंबर, 2020) के अनुसार मदुरा के कई स्कूल काम करने के लिए तैयार होने के लिए अपने स्नातकों पर ध्यान नहीं देते हैं। सीखने का मॉडल ज्ञान और नैतिकता को विकसित करने के बारे में अधिक है।

स्थानीय राजनीति और लोकतंत्र

स्थानीय राजनीति और लोकतंत्र के अध्ययन में शामिल हैं

1) स्थानीय राजनीति;

2) नागरिक समाज की स्वतंत्रता;

3) राजनीतिक दलों की भूमिका;

4) स्वतंत्रता और मीडिया की भूमिका;

5) जनसभाएं: विकास योजनाओं पर विचार-विमर्श की प्रभावशीलता (मुसरेंबांग);

6) सार्वजनिक शिकायत सेवाएं।

निष्कर्ष

सीकर जिले के ग्रामीण विद्यालय द्वारा उपयोग किए जाने वाले पठन कार्यक्रम को विद्यालय के पठन पाठ्यक्रम के पूरक के रूप में डिजाइन किया गया था, जो छात्रों को अंक संचय और इनाम प्रणाली के माध्यम से पढ़ने के लिए बाहरी रूप से प्रेरित करता था। पढ़ने के कार्यक्रम के ग्रामीण विद्यालय के कार्यान्वयन में, छात्रों को शुरू में उनके पढ़ने के स्तर को स्थापित करने के लिए कंप्यूटर प्रशासित मानकीकृत परीक्षण के माध्यम से मूल्यांकन किया गया था। फिर छात्रों को काल्पनिक और गैर-काल्पनिक किताबें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया जो उनके पढ़ने की उपलब्धि के स्तर पर या उससे थोड़ा ऊपर लिखी गई थीं। प्रत्येक पुस्तक के पढ़ने के पूरा होने पर, छात्रों को उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में सामग्री की उनकी समझ का आकलन करने के लिए एक मानकीकृत कंप्यूटर प्रशासित परीक्षा के माध्यम से परीक्षण किया गया था। कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया के माध्यम से सही उत्तर वाले प्रश्नों के लिए निर्धारित अंकों की संख्या प्रदान की गई। इस प्रक्रिया के माध्यम से, शिक्षकों के पास एक कम्प्यूटरीकृत प्रिंटआउट तक पहुंच थी, जो प्रत्येक छात्र द्वारा प्राप्त अंकों की संख्या और छात्र के बौद्धिक विकास को प्रकट करने के लिए एक बोधगम्य स्कोर को प्रकट करता था। स्कूल द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं ने छात्रों को विभिन्न पुरस्कारों के लिए अपने अंक "खर्च" करने की अनुमति दी। हालाँकि छात्रों की ग्रेडिंग के लिए रीडिंग पॉइंट्स का उपयोग करने के संबंध में स्कूल और समुदाय के कुछ गुटों के बीच परस्पर विरोधी विचार मौजूद थे, स्कूल ने इन रीडिंग पॉइंट्स का उपयोग छात्रों की अंतिम ग्रेड गणना के प्रतिशत के रूप में किया। स्कूल का दर्शन यह था कि छात्रों को अपने पढ़ने में सुधार करने के लिए, एक विजेता एथलेटिक टीम विकसित करने की तरह, अभ्यास और दोहराव की आवश्यकता थी। जबकि कुछ छात्र पढ़ने का आनंद लेते हैं और ऐसा करने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं, अन्य नहीं। छात्रों को एक निश्चित ग्रेड प्राप्त करने के लिए न्यूनतम अंकों की आवश्यकता होने से, सभी छात्रों को पढ़ने के लिए "मजबूर" किया गया, इस प्रकार सुधार और विकास के लिए आवश्यक अभ्यास और दोहराव प्राप्त किया गया, और सभी छात्र इनाम प्रणाली के विशेषाधिकारों का आनंद लेने में सक्षम थे। . स्कूल के डिजाइन में न्यूनतम आवश्यकताओं को पार करने के लिए बाहरी या आंतरिक रूप से प्रेरित होने वालों को प्रोत्साहित करते हुए प्रत्येक छात्र से न्यूनतम मात्रा में पढ़ने की आवश्यकता होती है। इन छात्रों ने सीकर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों पर पुरस्कार प्रणाली से सबसे बड़ा शैक्षिक लाभ प्राप्त किया।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

हिदायत, आर. (2017). राजनीतिक विचलन: इंडोनेशिया में सरकार के विकेंद्रीकृत मोड से सबक। सेज ओपन, 7(1), 2158244016686812।

ब्लेयर, एच। (2000)। परिधि पर भागीदारी और जवाबदेही: छह देशों में लोकतांत्रिक स्थानीय शासन। विश्व विकास, 28(1), 21-39। डीओआई: 10.1016/S0305-750X(99)00109-6।

रासैली, डब्ल्यू।, हिदायत, आर।, और प्रेयित्नो, एच। (2020, मई)। ग्रामीण गुणवत्ता शिक्षा सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्थानीय राजनीति को मजबूत करने पर। आईओपी सम्मेलन श्रृंखला में: पृथ्वी और पर्यावरण विज्ञान (वॉल्यूम 485, संख्या 1, पृष्ठ 012148)। आईओपी प्रकाशन। डीओआई: 10.1088/1755-1315/485/1/012148।

*Pineda-Escobar, M. A. (*2019)। 2030 एजेंडे को आगे बढ़ाना: कोलम्बिया में *SDG* कार्यान्वयन। कॉरपोरेट गवर्नेंस: द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बिजनेस इन सोसाइटी। डीओआई: 10.1108/सीजी-11-2017-0268।

ज़िंकर्नगेल, आर।, इवांस, जे।, और नीज, एल। (2018)। एसडीजी को शहरों में लागू करना: व्यापार हमेशा की तरह या एक नई सुबह? स्थिरता, 10(9), 1-18। डीओआई: 10.3390/*su*10093201